



भारत का राजपत्र



राष्ट्रपति व विधायक सभा

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

माण II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

—Section 3—So

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं१ १००

नई गिर्ल्सी, मंगलवार, मार्च 28, 1978/पैक 7, 1900

No. 1001

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1978/CHAITRA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे एक गह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
A separate heading is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कौशिं और सिंचार्ट संशोलन

(प्राचीन लिपाय)

三

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1978

सां का० लि० 197 (अ) /आ०ष०/गशा.—केन्द्रीय भरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त परिस्थितों का प्रयोग करते हुए, गशा (नियंत्रण) भारत, 1966 में घोर संगोष्ठन करने के लिए निम्नलिखित भारत करेंगी है, पर्याप्ति:—

1. (1) इस प्रावेश का नाम गला (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन प्रावेश
1978।

(2) यह सरक्स प्रवत होगा।

३. गजा (गियरण) भारत, १९६६ में।—

(i) खण्ड 4 में, परन्तुक के प्रधान निम्नलिखित एम्टुक मन्त्र स्थापित किये जाएंगे, प्रधानतः—

“परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति, खाण्डसारी चीमी के उत्पादक या उसके अभिकर्ता को ग़ज़े का विक्रय या विक्रय करने का करार नहीं करेगा और ऐसा कोई उत्पादक या उसका अभिकर्ता, अधृत 4 के प्रधान नियत कीमत से कम कीमत पर ग़ज़ा न तो खरीदेगा और न खरीदने का करार करेगा। परन्तु यह भी कि केंद्रीय सरकार या, केंद्रीय सरकार के प्रनुभोदन से राज्य सरकार, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के प्रधान रहते हुए, जो वह विनियिवृत्त करें, इस प्रकार नियत कीमत से उचित रिटेंशन प्रमाणात् कर सकेंगे।”

(ii) खण्ड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा। संक्षेप :—

“4क-वह रिक्वेट, जिसकी कटौती खाण्डसारी चीजों के उत्पादकों
द्वारा गश्ते के लिए संवत् भीमत से की जा सकती है।”

खाण्डसारी जीनी का उत्पादक या उसका अभिकर्ता, उसके द्वारा ब्रह्मीवे गाँ गम्भे के सिंण, गम्भा उपजकर्ता या गम्भा उपज-कर्ता सहकारी सोसाइटी को, यथास्थिति, या तो खण्ड 4 के द्वारीन नियंत्रण गम्भे भी नियंत्रण कीमत या उत्पादक अथवा उसके अभिकर्ता तथा गम्भा उपजकर्ता या गम्भा उपजकर्ता सहकारी सोसाइटी के मध्य सहमत कीमत (जिसे इसमें इसके पश्चात् सहमत कीमत कहा गया है) का संबंध करेगा, परन्तु—

(i) किसी रूप केन्द्र में परिषद्वत् ग्रन्थे के भास्त्रसे में—

(क) यदि आण्डसारी चीनी के उत्पादक द्वारा गंधे का परिवहन आण्डसारी एकम भें रेल द्वारा किया जाता है तो, यद्यपि, न्यूनतम कीमत या सहजत कीमत से बत्तीस पैसे प्रति किलोट का रिवेट दिया जाएगा; या

(ख) यदि खाण्डसारी जीती के उत्पादक द्वारा गँगे का परि-
वहन खाण्डसारी एकक में स्वयं अपने बाहर में सड़क
द्वारा किया जाता है तो, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या
सहमत कीमत से, मध्यिकतम बत्तीस पैसे प्रति किलोटि
के मध्यीन रहते हुए, 2.5 पैसे (झाई पैसे) ग्रामि किलोटि
प्रति किलो मीटर से अनधिक का रिटेंट इस गति के
मध्यीन रहते हुए दिया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार या
राज्य सरकार या कृषि निवेशक या गँगा आयरल

या जिला भविस्ट्रेट में, उनके अपनी आपनी अधिकारिता के भोतर, सम्बद्ध वय केन्द्र से खाण्डमार्ग एक तक की वास्तविक सूची और उस दशा में लाग प्रतिक्रियोंटर दर, जिसके प्रभाव पर खिट प्रभावित हिया गया है, के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र अभिप्राय किया गया द्वी।

स्पष्टीकरण — खण्ड (ख) के प्रयोगनार्थ आधे किलोमीटर गे कम दूरी को छोड़ विधा जाएगा तबकि आधे या आधे से अधिक मिलीमीटर की दूरी को एक किलोमीटर के रूप में गिना जाएगा;

- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या हृषि निदेशक या ग्राम प्रायुक्त या जिला मणिस्टेट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, खाण्डसारी एकको को जले हुए गंगे के लिए, यथास्थिति न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में उपयुक्त रिवेट अनुशासन कर सकेगा किन्तु हस शर्त पर कि इस प्रकार अनुशासन रिवेट जले हुए गंगे से खाण्डसारी बीनी की प्राप्ति में प्राक्क्रियत कभी के कारण कीमत में हुई कमी से अधिक न हो,

(iii) जहा गंगा गढ़ों से लाया जाता है और वैसे ही तोला जाता है वहाँ केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, या हृषि निदेशक या गंगा प्रायुक्त या जिला मणिस्टेट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर आवृत्त वाली सामग्री के भार के सम्बन्ध में, 0.625 किलोग्राम प्रति किलोट गंगे से अनश्विक तक का उचित रिवेट अनुशासन कर सकेगा; और

(iv) केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किन्हीं अन्य कारणों से यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में उचित रिवेट अनुशासन कर सकेगा।”

[म० ३/१/७७-चीनी नीति (डेस्क-ii)]

सी०एन०राधवन,
संयक्त सचिव।

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1978

G.S.R. 197(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Second Amendment Order, 1978.
(2) It shall come into force at once.
 2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966,—
 - (i) in clause 4, after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided further that no person shall sell or agree to sell sugarcane to a producer of khandsari sugar or his agent, and no such producer or his agent shall purchase or agree to purchase sugarcane, at a price lower than that fixed under clause 4.

Provided also that the Central Government or, with the approval of the Central Government, the State Government, may in such circumstances and

subject to such conditions as it may specify allow a suitable rebate in the price so fixed".

- (ii) after clause 4, the following clause shall be inserted, namely :—

"4A. Rebate that can be deducted from the price paid for sugarcane by producers of khandsari sugar :—

A producer of khandsari sugar or his agent shall pay, for the sugarcane purchased by him, to the sugarcane grower or the sugarcane growers' cooperative society, either the minimum price of sugarcane fixed under clause 4, or the price agreed to between the producer or his agent and the sugarcane grower or the sugarcane growers' cooperative society, as the case may be (hereinafter referred to as the agreed price) :

Provided that—

- (i) in the case of sugarcane delivered at any purchase centre,—

(a) if the sugarcane is transported to the khandsari unit by the producer of khandsari sugar by rail, a rebate of thirty-two paise per quintal shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be; or

(b) if the sugarcane is transported to the khandsari unit by road by the producer of khandsari sugar in his own transport, a rebate, not exceeding 2.5 paise (two and half paise) per quintal, per kilometer, subject to a maximum of thirty-two paise per quintal, shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be, subject to the condition that a certificate regarding the actual distance from the purchasing centre concerned to the khandsari unit and the rate per kilometer applicable in that case, on the basis of which the rebate is charged, is obtained from the Central Government or the State Government or the Director of Agriculture or the Cane Commissioner or the District Magistrate within their respective jurisdiction.

Explanation : For the purpose of clause (b) the distance of less than half a kilometer shall be ignored while a distance of half or more than half a kilometer, shall be counted as one kilometer;

- (ii) the Central Government or the State Government or the Director of Agriculture or the Cane Commissioner or the District Magistrate may allow a suitable rebate in the minimum price or the agreed price, as the case may be, for burnt cane supplied to khandsari units within their respective jurisdiction, subject to the condition that the rebate so allowed does not exceed the reduction in price on account of the estimated shortfall in the recovery of khandsari sugar from burnt cane;
 - (iii) where the sugarcane is brought bound in bundles and weighed as such, the Central Government or, with the approval of the Central Government, the State Government or the Director of Agriculture or the Cane Commissioner or the District Magistrate within their respective jurisdiction, may allow a suitable rebate in regard to the weight of the binding material not exceeding 0.625 kilograms per quintal of sugarcane; and
 - (iv) the Central Government or, with the approval of the Central Government, the State Government, may allow a suitable rebate in the minimum price or the agreed price, as the case may be, for any other reasons to be specified by the Central Government or the State Government, as the case may be."

[No. 3/4/77-SPY (DESK II)]
C. N. RAGHAVAN, Joint Secy.